

520

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.6(29)नवि/3/2004


जयपुर दिनांक: 03.12.07

:: आदेश ::

राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.6(29)नवि/3/2004 दिनांक 27.10.2005 में बिन्दु संख्या-1 में प्रावधान किया हुआ है कि अवाप्तशुदा कृषि भूमि के बदले 20 प्रतिशत आवासीय एवं 5 प्रतिशत व्यावसायिक विकसित भूमि आवंटित की जायेगी।

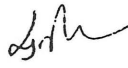
उक्त परिपत्र में बिन्दु संख्या-1 में निम्न दिशा-निर्देश जोड़े जाते हैं :-

1. स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आने वाली अवाप्तशुदा भूमि हेतु
 - a. आवासीय/आवासीय भूमि की अवाप्ति के बदले 40 प्रतिशत आवासीय एवं 10 प्रतिशत व्यावसायिक भूमि आवंटित की जाये
 - b. वाणिज्यिक भूमि की अवाप्ति के बदले 50 प्रतिशत वाणिज्यिक भूमि आवंटित की जाये
 - c. 90 बी की पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न हुई भूमि के लिए 30 प्रतिशत आवासीय एवं 7.5 प्रतिशत व्यावसायिक भूमि आवंटित की जाये।


(प्रकाश सिंह)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, माननीय राज्यमंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
6. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
8. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
9. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
10. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग।
11. शासन उप सचिव, नगरीय विकास विभाग।
12. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त।
13. रक्षित पत्रायली।


शासन उप सचिव

(52)